## उप्र में गन्ना पेराई दिसंबर तक

उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावों के बीच इस बार भी राज्य में गन्ना पेराई सत्र के दिसंबर से पहले शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने गन्ना पेराई सत्र 1 नवंबर से लेकर 15 नंवबर के बीच शुरू कर देने के दावे करते हुए चीनी मिलों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। चीनी मिलों की सुस्त तैयारी को देखते हुए इस बार भी पेराई दिसंबर के दूसरे सप्ताह से पहले शुरू होने के आसार नजर नही आ रहे हैं। पेराई में देरी के चलते किसान नेता इस बार भी बड़ी तादाद में गन्ना किसानों को अपनी उपज कोल्हू मालिकों को बेचना तय मान रहे हैं। बीते साल पेराई शुरू होने में हुई देरी के चलते किसानों को अपना गन्ना क्रशर और कोल्हू मालिकों को कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ा था। पृष्ठ 6

# उप्र में गन्ना पेराई सत्र में देरी

## पेराई दिसंबर के दूसरे सप्ताह से पहले शुरू होने के आसार नहीं

**बीएस संवाददाता**
लखनऊ, 13 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावों के बीच इस बार भी राज्य में गन्ना पेराई सत्र के दिसंबर से पहले शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

प्रदेश की समाजवादी सरकार ने गन्ना पेराई सत्र 1 नवंबर से लेकर 15 नंवबर के बीच शुरू कर देने के दावे करते हुए चीनी मिलों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि चीनी मिलों की सुस्त तैयारी को देखते हुए इस बार भी पेराई दिसंबर के दूसरे सप्ताह से पहले शुरू होने के आसार नजर नही आ रहे हैं। पेराई को लेकर हो रही देरी के चलते किसान नेता इस बार भी बड़ी तादाद में गन्ना किसानों को अपनी उपज कोल्हू मालिकों को बेचना तय मान रहे हैं। गौरतलब है कि बीते साल पेराई शुरू होने में हुई देरी के चलते बड़ी तादाद में किसानों को अपना गन्ना क्रैशर और कोल्हू मालिकों को कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ा था।

उधर सरकार ने पेराई सत्र शुरू करने के लिए चीनी मिलों को 1 नवंबर की समय सीमा दे दी है, पर बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए पेराई सत्र की जल्द शुरुआत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस बार प्रदेश में गन्ने का रकबा भी लगभग 10 फीसदी घटा है। दरअसल बीते दो सालों के अनुभव और गन्ना किसानों के भुगतान के संकट को देखते हुए चीनी मिलें सरकार पर गन्ना खरीद के मूल्य को लेकर दबाव बना रही हैं। चीनी मिलें पेराई शुरू होने से पहले गन्ना मूल्य तय करने की मांग करते हुए इसे रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रही हैं। रंगराजन समिति ने गन्ना मूल्य को चीनी मिलों के लाभ से जोड़ने की सिफारिश की थी।

**उत्तर प्रदेश की निजी मिलों पर बीते साल के पेराई सत्र का लगभग 3000 करोड़ रुपये बकाया**

बीते दो साल से चीनी मिलों की ओर से गन्ना बकाया मूल्य में हो रही देरी की वजह गन्ने की ऊंची कीमत को बताते हुए इस बार मूल्य निर्धारण से पहले सरकार से अपने सुझावों पर अमल करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की निजी मिलों पर बीते साल के पेराई सत्र का लगभग 3000 करोड़ रुपये बकाया है।

हालांकि चीनी मिलों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश की निजी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2013-14 के लिए घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एसएपी) के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा गन्ने पर क्रय कर की छूट, चीनी पर प्रवेश कर की छूट एवं सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति के मद में 11.03 रुपये प्रति क्विंटल की दी गई रियायतों के अलावा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को अवशेष 8.97 रुपये में से 6 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता गन्ना मूल्य के भुगतान के प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिपूर्ति के रूप में देने की घोषणा की थी। यह रियायत निजी क्षेत्र की उन्हीं चीनी मिलों को दी जाएगी, जो शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान कर देंगी। बकाया 2.97 रुपये प्रति क्विंटल निजी क्षेत्र की चीनी मिलें स्वयं वहन करेंगी।

Business Standard
14-10-14